International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

राजस्थान में मेवाड़ की राजनैतिक भागीदारी एवम् प्रभाव

(प्रथम आम चुनाव–1952 से 2018)

शोध निर्देशक
डॉ० भानु कपिल
इतिहास विभाग
बी. एन. विश्वविद्यालय
उदयपुर (राजः)

शोधार्थी
सुरेश जोशी
इतिहास विभाग
बी. एन. विश्वविद्यालय
उदयपुर (राजः)

सम्पूर्ण भारत वर्ष में मेवाड़ रियासत का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान और गौरवशाली इतिहास रहा है। यहां के शासक "हिन्दुआ सूरज" कहलाते थे। मेवाड़ के महाराणा भगवान राम के बड़े पुत्र कुश के वंशज माने जाते है। मेवाड़ के शासक पहले (सूर्यवंशी, फिर गुहिलोत और उसके बाद सिसोदिया नाम से प्रसिद्ध हुए। छठी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में गुहादित्य आनंदपुर से मेवाड़ आया था। बिना किसी विवाद, बिना किसी अप्रिय प्रसंग तथा किसी राजनीतिक उठापठक के संसार की सबसे प्राचीन एवं 1400 साल पुरानी मेवाड़ रियासत का राजस्थान राज्य संघ में विलोपन हो जाना, किसी आश्चर्य से कम नहीं था। स्वतंत्र भारत में पृथक से अस्तित्व बनाय रह सकने योग्य उदयपुर राज्य का, किसी बृहत् प्रशासनिक इकाई में विलय उस काल की सबसे बड़ी राष्ट्रीय घटना थी । इस घटना ने एक ओर तो पृथक रहने के लिये तरह–तरह के हथकडे अपना रही बडो रियासतों की नींद उड़ा दी और दूसरी ओर भारत सरकार को सुविधाजनक स्थिति में ला दिया। अब सरदार पटेल आसानी से भारत की किसी भी बड़ी से बड़ी रियासत को अपनी निकटतम बृहत्तर प्रशासनिक इकाई में विलय के लिये कह सकते थे।

महाराणा भूपालसिंह को राजप्रमुख, कोटा महाराव भीमसिंह को वरिष्ठ उप राजप्रमुख बूंदी एवं डूंगरपुर के राजाओं को कनिष्ठ उपप्रमुख बनाया गया। मेवाड़ प्रजामण्डल के प्रमुख नेता माणिक्यलाल वर्मा को राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 18 अप्रैल 1948 को जवाहलाल नेहरू हारा उद्घाटन किया गया।[1]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

राजस्थान जो पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था, 22 रियासतों के एकीकरण के परिणामस्वरूप निर्मित हुआ, आजादी के पूर्व राजस्थान एक राजनीतिक ईकाई के रूप में संगठित नहीं था। सभी रियासतों के पदक्रम, शासन प्रणालियां, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक पद्धतिया अलग–अलग थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयासो के परिणामस्वरूप कुछ रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांगे उठाई जाने लगी थी। विधानमंडल की स्थापना के संदर्भ में रियासतों की राजनीतिक गतिविधिया अत्यन्त सीमित मात्रा में थी। कुछ प्रगतिशील रियासतें ऐसी भी थी जहां के शासकों ने विधानमंडलों की स्थापना किसी न किसी रूप में कर दी थी। हालांकि इन विधानमंडलों का नाम, स्वरूप, आकार, अधिकार, कार्य व्यवस्था आदि विभिन्न प्रकार के थे लेकिन उनकी स्थापना से इंकार नहीं किया जा सकता।[2]

प्रथम विधानसभा का गठन – प्रथम विधानसभा गठन मार्च, 1952 में हुआ। सदन 160 स्थानों में से 82 कांग्रेस, 24 रामराय परिषद, 8 जनसंघ, 2 हिन्दू महासभा, 7 लोक परिषद, किसान मजदूर दल तथा समाजवादी दल को एक एक तथा 35 सीटें निर्दलीय को मिली। टीकाराम पालीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे के नेतृत्व में सरकार का निर्माण हुआ। 1 नवम्बर 1952 में मुख्यमंत्री पद पर जयनारायण व्यास का चुनाव कर लिया गया। कांग्रेस दल में गुटबंदी के कारण जयनारायण व्यास का सिंहासन भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। कांग्रेस के युवा नेता मोहनलाल सुखाड़िया ने जयनारायण व्यास को नेता पद की चुनौती दी जिसमें जयनारायण व्यास 8 मतों से पराजित हो गए। राजस्थान का नेतृत्व युवा व्यक्तित्व मोहनलाल सुखाड़िया के हाथ में आ गया। इस प्रकार प्रथम विधानसभा कार्यकाल में तीन चेहरे मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए।[3]

प्रथम विधानसभा में 160 स्थानों में से 16 अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित थे। प्रथम विधानसभा के तीसरे मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाडिया मेंवाड़, उदयपुर के निवासी थे। प्रथम विधानसमा के अपने प्रारम्भिक चरण में ही महत्वपूर्ण विषयों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

और कानूनों के एकीकरण, जमीदारियों के उन्मूलन और जमीन का स्वामित्व राज्य में निहित मानते हुए काश्तकारों को असली हक दिलाने के विधेयक पारित हुए।

द्वितीय विधानसभा का गठन – द्वितीय विधानसभा का गठन 1957 ई. में हुआ। इस चुनाव में कुल 176 सीटों में से कांग्रेस को 119, रामराज्य परिषद को 17, भारतीय जनसंघ को 6, साम्यवादी दल को एक, प्रजा समाजवादी दल को एक तथा निर्दलीय विधायकों को 32 सोटें मिली। मोहनलाल सुखाडिया के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। दूसरी विधानसभा में 28 स्थान अनुसूचित जाति तथा 12 स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित थे। दूसरी विधानसभा में पहली बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में लाया गया। कृषि विकास, उद्योग–धन्धो, ग्रामोत्थान, भूमि सुधार, उच्च शिक्षा, सहकारिता एवं समाज सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कानून पारित हुए।[4]

तीसरी विधान सभा का गठन – तीसरी विधानसभा का गठन मार्च 1962 में हुआ। सदन की कुल 176 सीटों में से 88 सीटों पर कांग्रेस जीती। स्वतंत्र दल को 36 स्थान प्राप्त हुए। मोहनलाल सुखाडिया के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। तीसरी विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 28, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 स्थान सुरक्षित थे। राजस्थान के विधायी इतिहास में तीसरी विधानसभा में सर्वाधिक मत्रीपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।[5]

चतुर्थ विधानसभा का गठन – चतुर्थ विधानसभा का गठन 1967 में हुआ। आजादी के बाद पहली बार किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, समाजवादी दल तथा कांग्रेस सदन में एक बड़े दल के रूप में उभरी लेकिन उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। मोहनलाल सुखाडिया को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया परन्तु व्यापक विरोध हुआ। जौहरी बाजार जयपुर में पुलिस गोली में 11 व्यक्ति मारे गए। राज्यपाल ने राज्य में

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की और 13 मार्च, 1967 को राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जो 44 दिन लागु रहा। दल बदल के कारण कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने। मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के बाद बरकतुल्ला खां को मुख्यमंत्री बनाया गया।[6]

पांचवी विधानसभा का गठन – पाचवी विधानसभा की 184 सीटों के लिए 6 से 11 मार्च 1972 को चुनाव हुए। 184 सदस्यों में से कांग्रेस को 145 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। जनसंघ को 8, स्वतंत्र दल को 11, अन्य दल को 9 तथा निदलियो को 11 स्थानों पर सफलता मिली। बरकतुल्ला खां के निधन 11 अक्टूबर 1973 के बाद हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलायी गयी। पांचवी विधानसभा में 31 स्थान अनुसूचित जाति तथा 21 अनुसूचित जनजाति के सुरक्षित थे।

छठी विधान सभा का गठन – 1977 के विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रदेश विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया गया जिसके परिणामस्वरूप विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढकर 200 हो गई। 144 स्थान सामान्य, 32 क्षेत्र अनुसूचित जातियों तथा 24 क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित है। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी को 151 स्थानो पर विजय प्राप्त हुई। पूर्व सत्तारूढ़ कांग्रेस दल को सदन में मात्र 41 स्थानो पर जीत हासिल हुई। इस चुनाव में मात्र 6 निर्दलीय चुनाव जीते । इस विधान सभा में पहली बार गैर काग्रेसी भैरोसिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री चुने जाने तक वे प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं थे, उस समय वे मध्यप्रदेश से राज्य सभा के सदस्य थे। उन्होंने 18 अक्टूबर 1977 को छबड़ा (बांरा) से उप चुनाव में विजयी होकर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। महारावल लक्ष्मनसिंह विधानसभा के अध्यक्ष तथा कांग्रेस के रामचन्द्र चौधरी उपाध्यक्ष चुने गए। छठी विधानसभा का कार्यकाल सबसे छोटा 2 वर्ष 7 माह (15 जून 1977 से 17 फरवरी 1980) तक रहा। राज्य में 3 माह 17 दिन राष्ट्रपति शासन लागू रहा।[7]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

सातवीं विधानसभा का गठन – सातवी विधान सभा का गठन 1980 में हुआ। छठी विधानसभा भंग होने के फलस्वरूप प्रथम बार राज्य विधानसभा का मध्यावधि चुनाव हुआ। काग्रेस को चुनाव में 200 में से 133 स्थानो पर सफलता मिली, भाजपा को 32 स्थानों पर सफलता मिली। सदन में भाजपा प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरा। भैरोसिंह शेखावत प्रतिपक्ष के नेता चुने गए। जगन्नाथ पहाडिया सर्वसम्मति से मुख्यमंत्रो बनाए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में पहाडिया ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जो लोकसभा के सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री चुने गए। बाद में वे भरतपुर जिले के वैर क्षेत्र से उपचुनाव मे विधायक चुने गए। बाद में शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री बने। 23 फरवरी 1985 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हीरालाल देवपुरा को 24 फरवरी 1985 को मुख्यमंत्री बनाया।[8]

आठवीं विधानसभा का गठन – आठवी विधानसभा का कार्यकाल 9 मार्च 1985 से 1 मार्च 1990 तक रहा। इस सभा के लिए 127 सामान्य, 17 महिलाएं, 23 अनुसूचित जनजाति तथा 33 अनुसूचित जाति के सदस्य चुने गए। काग्रेस को 113, भारतीय जनता पार्टी को 38, लोकदल को 27, जनता पार्टी को 10, माकपा को 1, निर्दलीय को 9 स्थान मिले। हरिदेव जोशी दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। हरिदेव जोशी के त्यागपत्र देने के बाद शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री बनाया गया। 8वीं विधानसभा के प्रारम्भ में विधानसभा अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा तथा उपाध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी चुने गए।

नवम् विधानसभा का गठन – 9वी विद्यानसभा का गठन 2 मार्च 1990 को हुआ तथा विघटन 15 दिसम्बर 1992 को हुआ। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 85, जनता दल को 54, कांग्रेस को 50, माकपा को 1, निर्दलीय को 9 स्थानो पर विजय हासिल हुई। प्रदेश में प्रथम भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ। 4 मार्च 1990 को भरोसिंह शेखावत मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शेखावत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 6 दिसम्बर 1992 को

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

अयोध्या घटना काण्ड के बाद 15 दिसम्बर 1992 को प्रदेश की भाजपा सरकार को संविधान के अनुच्छेद 356 (2) का सहारा लेकर बरखास्त कर विधान सभा को भंग कर दिया गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया । 16 मार्च 1990 को भाजपा के हरिशंकर भाभड़ा 9वीं विधानसभा के अध्यक्ष तथा यदुनाथ सिंह उपाध्यक्ष चुने गये । सदन में हरिदेव जोशी प्रतिपक्ष के नेता चुने गये।[9]

दसवीं विधानसभा का गठन – दसवी विधानसभा के लिए 11 नवम्बर 1993 को मतदान हुआ। भाजपा को 95, कांग्रेस को 76, माकपा को 1, जनतादल को 6 एवं निर्दलीय 21 स्थानो पर विजयी रहे। भाजपा के भैरोसिंह शेखावत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। भैरोसिह शेखावत ने कई किश्तों में मंत्रिमण्डल का विस्तार किया। जुलाई 1998 तक इस विस्तार योजना के कारण मंत्रीमडल सदस्य संख्या 40 तक पहुंच गई।[10]

ग्यारहवीं विधानसभा का गठन – ग्यारहवी विधानसभा का गठन 1998 में हुआ। भाजपा सरकार को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने 153 स्थानों पर विजय श्री अर्जित कर ऐतिहासिक रिकार्ड कायम किया। 197 सीटों पर हुए मतदान में भाजपा को मात्र 33 स्थान ही प्राप्त हुए। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री चुने गए। परसराम मदेरणा को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। भैरोसिह शेखावत विपक्ष के नेता चुने गए।[11]

बारहवी विधानसभा का गठन – 12वी विधानसभा के चुनाव 1 दिसम्बर 2003 को सम्पन्न हुए। प्रदेश की 200 सीटों के लिए चुनाव में प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार को हार का सामना करना पड़ा। 12वीं विधानसभा में कांग्रेस को मात्र 56 सीटों पर ही सन्तोष करना पड़ा। वही भाजपा को 120 सीटे प्राप्त हुई। इनेलो को 4, बसपा को 2, जनता दल को 2, लोक जन शक्ति को 1, माकपा को 1, सामाजिक न्यायमंच को 1, और निर्दलीय 13 स्थानों पर विजयी रहे। भाजपा विधायक दल की बैठक में श्रीमती वसुन्धरा राजे विधायक दल का नेता चुनी गई तथा 8 दिसम्बर 2003 को श्रीमती राजे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री का पद महिला ने प्राप्त किया। बारहवी विधानसभा के चुनाव सभी

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

200 विधानसभा सीटो पर इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) द्वारा करवाये गये। चुनाव में तैनात कर्मचारियो को पोस्टल–बेटल (डाक–मतपत्र) के माध्यम से मतदान करने का अधिकार दिया गया।[12]

तेरहवीं विधानसभा चुनाव 2008 – राजस्थान में 13वीं विधानसभा के चुनाव 4 दिसम्बर 2008 को सम्पन्न हुए। जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 96, भाजपा को 78, बहुजन समाजवादी पार्टी को 6, निर्दलीय 14 और मार्क्सवादी पार्टी को 3, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी 1, जनतादल 1, समाजवादी पार्टी 1 सींटें मिली। अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री बने।[13]

क्र.सं.	विधानसभा क्षेत्र	निर्वाचित सदस्य	पार्टी
1.	गोगुन्दा ST	मांगीलाल गरासिया	कांग्रेस
2.	झाड़ौल ST	बाबूलाल खराड़ी	बीजेपी
3.	खेरवाड़ा ST	दयाराम परमार	कांग्रेस
4.	उदयपुर ग्रामीण ST	सज्जन कटारा	कांग्रेस
5.	उदयपुर	गुलाबचन्द कटारिया	बीजेपी
6.	मावली	पुष्करलाल डांगी	कांग्रेस
7.	वल्लभ नगर	गजेन्द्रसिंह शक्तावत	कांग्रेस
8.	सलुम्बर ST	रघुवीर मीणा	कांग्रेस
9.	धरियावद ST	नागराज मीणा	कांग्रेस

स्त्रोत – राजस्थान विधान सभा चुनाव 2008, निर्वाचन विभाग, जयपुर (राज.)

चौदहवीं विधानसभा चुनाव 2013 – राज्य में 1 दिसम्बर 2013 को विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुए। कुल 199 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 163, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 21, राष्ट्रीय जनता पार्टी को 3 तथा निर्दलीय 9 उम्मीदवार विजयी रहे। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनीं।[14]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

क्र.सं.	विधानसभा क्षेत्र	निवाचित सदस्य	पार्टी
1.	गोगुन्दा	प्रतापलाल भील	बीजेपी
2.	झाड़ौल	हीरालाल	कांग्रेस
3.	खेरवाड़ा	नानालाल अहारी	बीजेपी
4.	उदयपुर ग्रामीण	फूलसिंह मीणा	बीजेपी
5.	उदयपुर	गुलाबचन्द कटारिया	बीजेपी
6.	मवली	डालीचन्द डांगी	बीजेपी
7.	वल्लभ नगर	रणधीरसिंह भीण्डर	निर्दलीय
8.	सलुम्बर	अमृतलाल मीणा	बीजेपी
9.	धरियावद	गौतमलाल	बीजेपी

स्त्रोत – राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013 निर्वाचन विभाग जयपुर (राज.)

पन्द्रहवीं विधानसभा चुनाव 2018 – 7 दिसम्बर 2018 को राजस्थान में विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 100 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई। भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें जीती। निर्दलीय 13, बहुजन समाजवादी पार्टी 6, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 3, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 2, भारतीय ट्राईबल पार्टी 2, राष्ट्रीय लोकदल ने 1 सीट पर विजय हासिल की। अशोक गेहलोत तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने।[15]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

क्र.सं.	विधानसभा क्षेत्र	निर्वाचित सदस्य	पार्टी
1.	गोगुन्दा ST	प्रतापलाल भील	बीजेपी
2.	झाड़ौल ST	बाबूलाल खराड़ी	बीजेपी
3.	खेरवाड़ा ST	दयाराम परमार	कांग्रेस
4.	उदयपुर ग्रामीण ST	फूलसिंह मीणा	बीजेपी
5.	उदयपुर	गुलाबचन्द कटारिया	बीजेपी
6.	मावली	धर्मनारायण जोशी	बीजेपी
7.	वल्लभ नगर	गजेन्द्रसिंह शक्तावत	कांग्रेस
8.	सलुम्बर ST	अमृतलाल मीणा	बीजेपी
9.	धरियावद ST प्रतापगढ़	गौतमलाल मीणा	बीजेपी

स्त्रोत :– राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018, निर्वाचन विभाग, जयपुर (राज.)

राज्य राजनीति में मेवाड़ की भागीदारी – प्रथम आम चुनाव 1952 से 2018 तक मेवाड़ का राज्य राजनीति में महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। प्रथम आम चुनाव से चौथी विधानसभा तक मेवाड़ से श्री मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में मोहनलाल सुखाड़िया राज्य की राजनीति के केन्द्र बिन्दु रहते हुए उन्होंने राजस्थान का अभूतपूर्व विकास किया। मेवाड़ का राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहां से कई विधायक केबिनेट एवं राज्यमंत्री बने जिन्होंने राज्य के विधायी शक्तियों में अहम भागीदारी निभाई।[16]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

क्रसं	चुनाव वर्श	चुनाव क्षेत्र	विजयी उम्मीदवार	वर्ग	पार्टी का नाम
1	1952–57	बांसवाड़ा	भीखा भाई	अजजा	कॉग्रेस
		उदयपुर	बलवन्त सिंह	सामान्य	कॉग्रेस
2	1957–62	बांसवाड़ा	भोगजी भाई	अजजा	कॉग्रेस
		उदयपुर	माणिक्यलाल वर्मा	सामान्य	कॉग्रेस
3	1962–67	बांसवाड़ा	रतनलाल	अजजा	कॉग्रेस
		उदयपुर	धूले”वर	अजजा	कॉग्रेस
4	1967–70	बांसवाड़ा	हीरजी	अजजा	कॉग्रेस
		उदयपुर	धूले”वर	अजजा	कॉग्रेस
5	1971–77	बांसवाड़ा	हीरालाल	अजजा	कॉग्रेस
		उदयपुर	लालिया	अजजा	कॉग्रेस
6	1977–79	बांसवाड़ा	हीरा भाई	अजजा	भारतीय लोकदल
		उदयपुर	भानु कुमार शास्त्री	सामान्य	भारतीय लोकदल
7	1980–1984	बांसवाड़ा	हीरा भाई	अजजा	कॉग्रेस
		उदयपुर	मोहनलाल सुखाड़िया	सामान्य	कॉग्रेस
8	1984–89	बांसवाड़ा	प्रभुलाल रावत	अजजा	कॉग्रेस
		उदयपुर	इन्दुबाला सुखाड़िया	सामान्य	कॉग्रेस
9	1989–91	बांसवाड़ा	हीरा भाई	अजजा	जनता दल
		उदयपुर	गुलाबचन्द कटारिया	सामान्य	भाजपा
10	1991–96	बांसवाड़ा	प्रभुलाल रावत	अजजा	कॉग्रेस
		उदयपुर	गिरजा व्यास	सामान्य	कॉग्रेस

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

12	1996–98	बांसवाड़ा	ताराचन्द भगोरा	अजजा	कॉग्रेस
		उदयपुर	गिरजा व्यास	सामान्य	कॉग्रेस
13	1998–99	बांसवाड़ा	महेन्द्रजीत सिंह मालवीया	अजजा	कॉग्रेस
		उदयपुर	शान्तिलाल चपलोत	सामान्य	कॉग्रेस
14	1999–2004	बांसवाड़ा	ताराचन्द भगोरा	अजजा	कॉग्रेस
		उदयपुर	गिरजा व्यास	सामान्य	कॉग्रेस
15	2004–2009	बांसवाड़ा	धनसिंह रावत	अजजा	भाजपा
		उदयपुर	किरण माहे"वरी	सामान्य	भाजपा
16	2009–2014	बांसवाड़ा	ताराचन्द भगोरा	अजजा	कॉग्रेस
		उदयपुर	रघुवीरसिंह मीणा	अजजा	कॉग्रेस
17	2014–2019	बांसवाड़ा	मानशंकर निनामा	अजजा	भाजपा
		उदयपुर	अर्जुनलाल मीणा	अजजा	भाजपा

प्रथम आमचुनाव 1952–2018

लोकसभा चुनाव में मेवाड़ राज्य की भागीदारी

स्त्रोत – www.indiavotes.com, General Election Loksabha

प्रजामण्डल की स्थापना – जयपुर, 15 अगस्त राजस्थान में दासता से मुक्ति के प्रयास अहिंसक असहयोग आंदोलन की शुरुआत बिजोलिया के किसान आंदोलन से हुई थी। उस समय राजस्थान की जनता पर अंग्रेजों की हुकूमत की बेड़ियां तो थी हीं, साथ ही उन्हें यहां के शासकों एवं जागीरदारों के दमन का भी सामना करना पड़ा। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार राजस्थान के शासकों ने उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजों से संधि कर ली जिससे उन्हें बाहरी आक्रमणों एवं मराठो के आतंक से मुक्ति मिल गई थी। निर्भय हो जाने के कारण इन राजाओं ने आम जनता पर नए–नए करों का बोझ डालना प्रारंभ कर दिया।[17]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

मेवाड़ प्रजामण्डल (24 अप्रेल 1938) – मेवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना का श्रेय माणिक्यलाल वर्मा को जाता है। उनके प्रयासों से उदयपुर में 24 अप्रल 1938 को बलवंतसिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना की गयी। 25–26 नवम्बर 1941 में मेवाड़ प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर की शाहपुरा हवेली में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ, जिसका उद्घाटन जे.बी. कृपलानी ने किया। प्रजामंडल ने बेगार एवं बलेठ प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। दिनांक 9 अगस्त 1942 को शुरू किये गए भारत छोड़ों आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया।[18]

प्रजामंडल के सामाजिक सुधार कार्य – प्रजामंडल के सभी नेताओं एंव कार्यकर्ताआ ने गॉव–गॉव, शहर–शहर जा कर सक्रिय रूप से बाल विवाह, कन्या वध, पर्दा प्रथा मृत्यु–भोज, बहुविवाह–प्रथा, दहेज–प्रथा, डाकन–प्रथा, छुआछूत, ऊँच–नीच का भेदभाव आदि सभी कुरीतियों का पुरजोर विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, विवाह की अधिक आयु आदि का पुरजोर समर्थन ही नहीं किया, बल्कि इस सन्दर्भ में जनजागृति भी पैदा की। इसी प्रकार शराबबंदी आंदोलन, नशीली वस्तुओं का प्रचार रोकना,मजदूरों के हितों के लिए कानून बनवाना, प्रजा की भलाई के कार्य करना, चरखा एवं खादी उत्पादन केन्द्र स्थापित करना, बाढ व अकाल राहत कार्यो में जन सहयोग जैसे अनेक कार्य हाथ में लेकर जनता को अपने साथ मिला लिया।[19]

शिक्षा प्रसार का कार्य – प्रजामंडल आंदोलन का एक सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य जन सामान्य की शिक्षा का प्रचार–प्रसार रहा है। उनके द्वारा जगह–जगह रात्रि पाठशाला खोली गई गांव गांव व शहर में अनेक पाठशाला, दलितों के लिए कबीर पाठशाला खोली गई। लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला स्थापित की गई। प्रजामंडलों ने सभी नगरों ओर

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

कस्बों में पुस्तकालय, वाचनालय स्थापित कर संचालित किए गए। हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। हरिभाई किंकर ने महिला शिक्षा सदन (हटूंडी) स्थापित कर महिला शिक्षा के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया गया।

दलितोत्थान कार्य– प्रजामंडल के सभी नेताओं एंव कार्यकर्ताओं ने गॉव–गांव जाकर दलितोत्थान कार्य किये तथा प्रजामंडल के दौरान सभी जगह छुआछूत, ऊंच–नीच आदि के भेदभाव को मिटाया गया। दलितों को भी आंदोलन में सक्रिय रुप से सम्मिलित किया गया। अलवर में पंडित हरि नारायण ने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ गोकुल भाई भट्ट ने हरिजन सेवा संघ, भोगीलाल पंड्या ने हरिजन समिति, वर्मा जी ने मेवाड़ हरिजन सेवा संघ, रामनारायण चौधरी ने राजपूताना हरिजन संघ आदि। अनेक दलितोत्थान संस्थान स्थापित किये। इन्होनें दलितों में मद्यनिषेध, शिक्षा प्रसार, जन जागरण, मंदिर प्रवेश, गरीबी उन्मूलन सम्बन्धित आदि कार्य किये। इन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने का सराहनीय प्रयास किये गये।[20]

प्रजा मंडल आंदोलन के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव – देसी रियासतों में नागरिक अधिकारों की बहाली, उत्तरदायी शासन की स्थापना और राजनीतिक आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रांतीय शाखाओं के रूप में रियासतों में जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुए प्रजामंडल कहलाए। इसके द्वारा संचालित आंदोलन प्रजामंडल आंदोलन कहलाये। इन प्रजामंडल आंदोलनों ने राजनीतिक आंदोलन के साथ–साथ सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अत्यंत सराहनीय कार्यकिए गए ? इन आंदोलनों के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया गया। दलित उत्थान और आदिवासी उत्थान के कार्य किए गए।[21]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

राजनैतिक भागीदारिता में कमी –

1. **भील राज्य की मांग** – भील राज्य को राजस्थान, गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिलों को मिलाकर बनाने की मांग की जा रही है. ये जिले दक्षिणी राजस्थान के जिले डूंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ, अलिराजपुर, धार, पेटलावाद, इत्यादि जबकि गुजरात के पूर्वी जिले पंचमहल गोधरा, दाहोद और दक्षिणी जिला डांग और महाराष्ट्र के उत्तरी जिले जिसमें नाशिक, धुल आते है। भारत की जनगणना के हिसाब से देश में सन 1961 में 3 करोड़ की ट्राइबल आबादी थी जो कि 2011 की जनगणना में बढ़कर 10.42 करोड़ हो गयी गई। जिनमें दशकीय वृद्धि दर 23.7 प्रति"ात की है। भारत में सबसे अधिक जनजातियों की संख्या 14.7 प्रति"ात मध्यप्रदेश म रहती है इसके बाद महाराष्ट्र (10 प्रति"ात) और फिर तीसरे नंबर पर 9.2 प्रति"ात ओडिशा में रहती है। भील प्रदेश का आन्दोलन काफी पुराना है. भारतीय जनता पार्टी ने भील प्रदेश बनाने का समर्थन किया है।[22]

चार राज्यों के इन जिलों को मिलाकर है भील प्रदेश बनाने की मांग –

- **गुजरात** – बनासकांठा–सावरकांठा, अरावली–महिदसागर, वडोदरा–भरूच,सूरत और पंचमहल का हिस्सा, दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड़, दमन दीव, दादर नागर हवेली।
- **राजस्थान**–डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, जालोर–बाड़मेर–पाली का हिस्सा।
- **महाराष्ट्र** –जलगांव–नासिक और ठाणे का हिस्सा, नंदूरबाग, धुलिया और पालघर।
- **मध्यप्रदेश** –नीमच–मंदसौर,रतलाम और खंड़वा का हिस्सा, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन और बुरहानपुर।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

2. **राजस्थान जनजातीय उपयोजना क्षेत्र** – अनुसूचित जनजातियों के त्वरित विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1975–79) के दौरान एक वि"ोष रणनीति अपनायी गई। इस रणनीति को जनजातीय उपयोजना क्षेत्र कहा जाता है। जनजातीय उपयोजना का गठन राजस्थान में 1974–75 में दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय बाहुल्य जिले बांसवाड़ा–डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ तथा धरियावाद तहसीले और उदयपुर तथा सिरोही जिले की तहसीलें जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र थी उनको मिलाकर किया गया था। नई अधिसूचना 19 मई 2018 के अनुसार जनजातीय उपयोजना क्षेत्र का विस्तार किया गया है। जिसमें दक्षिणी राजस्थान के 8 जिलों की 31 तहसीलों को मिलाकर अनुसूचित क्षेत्र निर्मित किया गया है, जिसमें जनजातियों का सघन आवास है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या 45.51 लाख है जो इस क्षेत्र की जनसंख्या का 70.42 प्रति"ात है। इस क्षेत्र में आवासित जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया व डामोर प्रमुख है।[23]

3. **समानता मंच** – टीएसपी क्षेत्र में सामान्य ओबीसी वर्ग को आरक्षण की मांग को लेकर 10 साल पहले आंदोलन शुरू हुआ था। अगस्त, 2006 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आसपुर क्षेत्र में शुद्ध पेयजल योजना के उदघाटन कार्यक्रम को लेकर आई थी। उस समय समानता मंच ने अमृतिया गांव में मुख्यमंत्री के काफिले को रोक नारेबाजी की थी। इसको लेकर आसपुर थाने में समानता मंच संस्थापक संरक्षक दिग्विजयसिंह चुंडावत सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।समानता मंच टीएसपी एरिया में शामिल जिलों में एक–एक विधानसभा सीट सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित करने की मांग को लेकर पिछले डेढ़ दशक से आंदोलन कर रहा है। राज्य के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों के साथ ही उदयपुर ग्रामीण और सिरोही जिलों का कुछ हिस्सा टीएसपी एरिया में आते है।[24]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

4. **भारतीय ट्रायबल पाटी (संक्षिप्त रूप में BTP)** इस पार्टी का गठन गुजरात में किया गया। इसका गठन 2017 में छोटूभाई वसावा और महे"ा भाई वसावा द्वारा किया गया था। भारत के चुनाव आयोग द्वारा बीटीपी को ऑटो रिक्"ा चुनाव चिह्न आवंटित किया गया। दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय समुदाय मं बीटीपी का गहरा प्रभाव पड़ा है। इस पार्टी से सागवाड़ा विधानसभा से रामप्रसाद डिण्डोर तथा चौरासी विधानसभा डूंगरपुर से राजकुमार रोत विधायक चुने गये है।[25]
5. **भारत आदिवासी पार्टी (संक्षिप्त रूप में BAP)** राजस्थान भारत में स्थित एक राजनीतिक दल है। पार्टी का गठन 10 सितंबर 2023 में भारतीय ट्राइबल पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार रोत द्वारा किया गया था। भारत आदिवासी पार्टी ने 2023 के राजस्थान विधान सभा चुनाव में तीन सीटें और 2023 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में एक सीट जीतीं। पार्टी नेता रोत ने चौरासी विधानसभा क्षेत्र (राजस्थान) में उनसठ हजार से अधिक वोटों के ऐतिहासिक अंतर से जीत हासिल की।

तालिका संख्या 1
मेवाड़ में राजनैतिक भागीदारी

क्र. सं	जाति/ वर्ग	भागीदारी में वृद्धि	भागीदारी में कमी	कुछ कहा नहीं जा सकता	योग
1	ब्राह्मण	7	15	3	25
2	क्षत्रिय	5	16	4	25
3	वै"य	11	12	2	25
4	जनजाति	20	4	1	25
	योग	43	47	10	100

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

तालिका संख्या 1 को मेवाड़ में राजनैतिक भागीदारी बढ़ रहीं है या गिरावट आई है के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। प्रत्येक जाति वर्ग से 25–25 उत्तरदाताओं को अध्ययन में शामिल किया गया है। ब्राह्मण वर्ग से कुल चयनित 25 उत्तरदाताओं में से 15 उत्तरदाताओं का मत है वर्तमान में राजनैतिक आरक्षण की वजह से उनकी भागीदारी में कमी हुई है। 7 उत्तरदाताओं का मत है कि उनकी राजनैतिक भागीदारी बढ़ी है। जबकि 3 उत्तरदाताओं का मत है कि इस सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्षत्रिय एवं राजपूत उत्तरदाताओं के अनुसार सर्वाधिक 16 उत्तरदाताओं का मत है कि उनकी राजनैतिक भागीदारी में कमी हुई है।जबकि 5 उत्तरदाताओं का मत है कि उनकी राजनैतिक भागीदारी बढ़ी है। जबकि 4 उत्तरदाताओं का मत है कि इस सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता।[26]

वै"य वर्ग के कुल चयनित 25 उत्तरदाताओं में से 12 उत्तरदाताओं का मत है कि मेवाड़ की राजनीति में उनकी राजनैतिक भागीदारी कम हुई है। 11 उत्तरदाताओं का मत है वर्तमान में उनकी राजनैतिक भागीदारी बढ़ी है। 2 उत्तरदाताओं का मत है कि इस सम्बन्ध में कुछ कहा नही जा सकता।

स्वतन्त्रता के प"चात् जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जनजाति वर्ग के अनुसार राजनैतिक आरक्षण के तहत 20 उत्तरदाताओं का मत है कि मेवाड़ की राजनीति में उनकी शत–प्रति"ात भागोदारी बढ़ी है। 4 उत्तरदाताओं का मत है कि उनकी राजनीतिक भागीदारी में कमी हुई है। जबकि 1 उत्तरदाता का मत है कि इस सम्बन्ध कुछ कहा नहीं जा सकता।[27]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

तालिका संख्या 2

ब्रिटी"ा संरक्षण एवं आरक्षण का विभिन्न वर्गो पर प्रभाव

क्र. सं	जाति/ वर्ग	राजनीतिक प्रभाव	आर्थिक प्रभाव	समाजिक प्रभाव	अन्य	योग
1	ब्राह्मण	16	4	3	2	25
2	क्षत्रिय	19	3	2	1	25
3	वै"य	6	14	3	2	25
4	जनजाति	18	3	4	—	25
	योग	59	24	12	5	100

तालिका संख्या 2 को ब्रिटी"ा संरक्षण एवं आरक्षण का विभिन्न जातियों एवं वर्गो पर राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ब्राह्मण वर्ग से कुल चयनित 25 उत्तरदाताओं में से 16 उत्तरदाताओं का मत है कि ब्रिटी"ा संरक्षण एवं वर्तमान में आरक्षण व्यवस्था के कारण उनके राजनैतिक प्रभावों में कमी हुई है। 4 उत्तरदाताओं का मत है कि उनके आर्थिक प्रभावों में कमी हुई है। 3 उत्तरदाताओं का मत है कि वर्तमान में उनके सामाजिक प्रभावों में कमी हुई है। 2 उत्तरदाताओं का मत है कि उनके जीवन पर अन्य प्रभाव पड़े है।[28]

कुल चयनित 25 क्षत्रिय/राजपूत उत्तरदाताओं में से 19 उत्तरदाताओं का मत है कि ब्रिटी"ा संरक्षण एवं राजनीतिक आरक्षण की वजह से उनके राजनैतिक प्रभावों में कमी हुई है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

3 उत्तरदाताओं का मत है उनके आर्थिक प्रभाव कम हुए है। 2 उत्तरदाताओं का मत है कि उनके सामाजिक प्रभाव कम हुए है तथा एक उत्तरदाता का मत है कि संरक्षण एवं आरक्षण से सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा है।

कुल चयनित 25 वै"य उत्तरदाताओं में से 6 उत्तरदाताओं का मत है कि उनका राजनैतिक प्रभाव कम हुआ है। 14 उत्तरदाताओं का मत है कि उनके आर्थिक प्रभाव में कमी हुई है। 3 उत्तरदाताओं का मत है कि उनका सामाजिक प्रभाव कम हुआ है। 2 उत्तरदाताआ का मत है कि समग्र रूप से अन्य प्रभाव भी पड़े है। कुल चयनित 25 जनजाति उत्तरदाताओं में से 18 उत्तरदाताओं का मत है कि ब्रिटी"ा संरक्षण एवं आरक्षण से उनके राजनैतिक प्रभाव में वृद्धि हुई है और शत–प्रति"ात राजनैतिक आरक्षण का लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है। आरक्षण की वजह से वर्तमान में विधायक, सांसद और मंत्री आदि पदों पर आसीन है। 3 उत्तरदाताओं का मत है कि वर्तमान में उनके रहन–सहन, खान–पान और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। 4 उत्तरदाताओं का मत है कि राजनैतिक आरक्षण एवं आर्थिक वृद्धि के कारण उनकी सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हुई है।

ब्रिटी"ा संरक्षण के बाद धीरे–धीरे मेवाड की राजनीतिक धुरी क्षत्रिय वर्ग से अन्य वर्गो की ओर बढ़ी और स्वतन्त्रता के प"चात् राजनीतिक आरक्षण से निम्न जाति–वर्ग के लोग राजनैतिक पदों पर आसीन हुए तथा वर्षो से राजनीतिक केन्द्र बिन्दु रहे। राजपूत वर्ग एवं राज्य धीरे–धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण अपने पद, प्रतिष्ठा और सम्मान से रहित हो गये।[29]

भारतीय लोकतन्त्र निरन्तर विकास और सुदृढ़ीकरण की ओर अग्रसर है। मतदाताओं के परिपक्व निर्णय ने प्रत्येक आम चुनाव के बाद राजस्थान राजनीति को नये आयाम प्रदान किये। चुनाव निर्वाचित प्रतिनिधियों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाता है। इन्हीं प्रतिनिधियों के हाथों में देश और लोकतंत्र का भविष्य सुनिश्चित करते हुए उसकी निरतरता बनाये रखने में समस्त समाज का विश्वास होता है और इसी में समष्टि का बौद्धिक विकास भी समाहित

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

होता है। एक निर्वाचन की समीक्षा उसके बाद आने वाला निर्वाचन करता रहता है जिससे विकास बाधित न हो और समय की आवश्यकता के अनुसार उसमे गत्यात्मकता बनी रहे और लोकतंत्र का भविष्य सुनिश्चित रहे।

चुनाव का संबंध केवल प्रतिनिधियों के चयन तक ही सीमित नहीं है अपितु चुनाव जनता के लिए राजनीति में भाग लेने का एक मात्र माध्यम है इसी से जनता को न्यूनतम राजनीतिक सहभागिता निभाने का अवसर प्राप्त होता है। इसी से जनता में सरकार के प्रति एक सीमा तक अपनेपन और दायित्व की भावना बनी रहती है तथा वह शासकों के अधिकारों को वैद्यता भी प्रदान करते हैं। एडवर्ड शिल्स ने स्पष्ट किया है कि ''चुनाव क्रान्ति को अपने महत्व तथा अपनी भावुकता को सम्पूर्ण राष्ट्रों के प्रतीकों से जोड़ने में सहायक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

1. डॉ. सन्तोष कुमारी आसेरी (2013) "राजस्थान में प्रतिनिधि संस्थाओं का इतिहास " राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर, पृ.सं. 201 –202
2. डॉ. उम्मेदसिंह इन्दा (2005) "राजस्थान में स्वाधीनता संघर्ष राज्य शासन एवं राजनीति" राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर, पृ.सं. 145–150
3. डॉ. मोहनलाल गुप्ता (2016) "राष्ट्रीय राजनीति में मेवाड़ का प्रभाव'' महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन ट्रस्ट, उदयपुर पृ.सं. 269–270
4. डॉ. सन्तोष कुमारी आसेरी (2013) "राजस्थान में प्रतिनिधि संस्थाओं का इतिहास " राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर, पृ.सं. 201 –202
5. प्रो. एस.के. कपिल (2014)''राजपूताना : जनजागरण से एकीकरण''राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर। पृ.सं. 159–160
6. चौधरी रामनारायण, "बीसवी सदी का राजस्थान''
7. इलेक्शन एटलस – राजस्थान निर्वाचन विभाग (1952–2018)
8. कश्यप, सुभाष ''राज्यों की राजनीति एवं दल बदल की राजनीति''

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

9. प्रबोधन कार्यकम – राजस्थान विधानसभा सचिवालय जयपुर
10. राठौड़, प्रो. एल. एस. राठौड़ ''पॉलिटिकल एण्ड कॉन्स्टीट्युशन डवलपमेन्ट इन राजस्थान
11. राजस्थान विधान सभा चुनाव 2008, निर्वाचन विभाग, जयपुर (राज.)
12. राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013 निर्वाचन विभाग जयपुर (राज.)
13. राजस्थान विधानसभा चुनाव 2014 निर्वाचन विभाग जयपुर (राज.)
14. रामाश्रय राय व पॉल वेलास(1999) इण्डियन पॉलिटिक्स एण्ड 1998 इलेक"ान्स रीजनेलिज्म, हिन्दुत्व एण्ड स्टेट पॉलिटिक्स, नई दिल्ली : सेज पब्लिके"ान्स
15. आहूजा एन.एन.(1952–1998) इलेक्टोरेल पॉलिटिक्स एण्ड जनरल इलेक"ान्स इन इण्डिया नई दिल्ली, मितल पब्लिके"ान्स
16. मीनू राय (1994) इलेक"ान पॉलिटिक्स इन इण्डिया, नई दिल्ली : अनुसंधान व वि"ाद अध्ययन संस्थान, जयपुर,
17. आर.पी. व्यास (1995) आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर पृ.सं. 373–375
18. डॉ. एम.एस. जैन, आधुनिक राजस्थान का इतिहास पृ.सं. 378–379
19. शर्मा, डॉ. भद्रदत्त – 1981 भारत का संवैधानिक इतिहास, पृ.सं. 332–333
20. डॉ. उम्मेद सिह (2005) मे राजस्थान में स्वाधीनता संघर्ष, राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर, पृ.सं. 78–79
21. आर.पी.व्यास (1995) आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकदहमी, जयपुर पृ.सं. 373–374
22. बी.एल. पानगडिया , राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, पृ.सं. 101–103
23. डॉ.गोपीनाथ शर्मा (2004). आधुनिक राजस्थान का इतिहास, ग्रन्थ विकास जयपुर पृ.सं. 247–248

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

24. डॉ. उम्मेद सिंह (2005) राजस्थान मे स्वाधीनता संघर्ष राज्य शासक एवं राजनीति, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर . पृ.सं. 81–82
25. डॉ. एम.एस. जैन (2017) आधुनिक राजस्थान का इतिहास, राजस्थान अध्ययन केन्द्र, जयपुर पृ.सं. 338–339
26. डॉ. उम्मेदसिंह (2005) "राजस्थान के स्वाधीनता संघर्ष राज्यशासन एवं राजनीति, राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर, पृ.सं. 80–81
27. भण्डारी डॉ. विमलेश एवं आनन्दचंद (1971) भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास पृ.सं. 458–460
28. डॉ. गोपीनाथ शर्मा (2004) में आधुनिक राजाधान का इतिहास, ग्रन्थ विकास, जयपुर 134–135
29. वंश भास्कर भाग – 4, पृ.सं. 2917, 3040–54
30. फो.पो. लेक का पत्र वेलेजली को 8 दिसम्बर, 1863 रा.अ. कोट पो. गवर्नर जनरल पत्र का पत्र लेन को 18 जुलाई, 1903 रा.अ.
31. हैस्टिंग्ज़ के मिनिट्स, दिसम्बर 1815, पैरा 84–89,132,302,303, बंगाल सीक्रेट कन्सलटेशन अक्टूबर 11817, रा.अ विलियम के. मेटकाफ का जीवन, भाग–1 पृ. 459–460 मेहता लार्ड हेस्टिंगज़ पृ.सं. 126–127
32. डॉ. के. एस. गुप्ता/डॉ. गोपाल व्यास/डॉ. जेट ओसा (1998) ''राजस्थान का इतिहास'' (1433–1900 ई.)" शिवा पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, उदयपुर पृ.सं. 134–135
33. राजपूताना गजेटियर पृ.सं. 295–296
34. ओझा, सिरोही राज्य का इतिहास पृ.सं. . 283–291
35. वीर विनोद, भा.1, पृ.1342–1343
36. डॉ. गोपीनाथ शर्मा (2004) आधुनिक राजस्थान का इतिहास" ग्रन्थ विकास, जयपुर पृ. सं. 144–145

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 12, Dec- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

37. डॉ. उम्मेदसिंह इन्दा (2005) "राजस्थान में स्वाधीनता संघर्ष, राज्य शासन एवं राजनीति" राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर पृ.सं. 7–8
38. डॉ. एम.एस. जैन, ''आधुनिक राजस्थान का इतिहास'' पृ.सं. 59–60
39. डॉ. हेतसिह वघेला (2005) "राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा (प्रारम्भ से 1949 तक) विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ–सं. 182–184
40. एम. एस. मेहता : लार्ड हेस्टिंग्ज एण्ड द इण्डियन स्टेटस, पृ.सं. 178–179